

प्रेषक,

डी० सेन्थिल पाण्डेयन,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
चिकित्सा शिक्षा, निदेशालय  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक 14/3/2017

विषय:- राजकीय मेडिकल कालेज, हल्द्वानी के नवनिर्मित पुस्तकालय भवन में ए०सी०, फर्नीचर सीसीटीवी, नेटवर्किंग एवं लिफ्ट के कार्यों हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 26प/चि०शि०/82/2012/708 दिनांक 10.02.2016 एवं पत्र संख्या-26प/चि०शि०/82/2012/3248 दिनांक 20.06.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेज, हल्द्वानी के नवनिर्मित पुस्तकालय भवन में ए०सी०, फर्नीचर, सीसीटीवी, नेटवर्किंग एवं लिफ्ट के कार्यों हेतु टी०ए०सी० वित्त द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण/संस्तुत धनराशि रू० 12.17 लाख एंर उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अनुसार धनराशि रू० 166.32 लाख इस प्रकार कुल रू० 178.49 लाख की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्राविधानित धनराशि रू० 3.00 करोड में से अवशेष धनराशि रू० 2.00 करोड के सापेक्ष रू० 100.00 लाख (रू० एक करोड मात्र) धनराशि व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृत किया जा रहा है। इस संबंध में समस्त प्रचलित वित्तीय नियमों/शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
3. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाए जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृति धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।
4. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
5. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाए।
6. कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली-भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप कार्य कराया जाए।
7. विस्तृत आगणन से प्राविधानित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु संबंधित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगी।
8. स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाए। कार्य की प्रगति की निरंतर व गहन समीक्षा करते हुये कार्य को निर्धारित



समयसारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्ण करते हुए भवन विभाग को हस्तगत कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। विलम्ब या अन्य किसी भी दशा में आगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा। उक्त कार्य के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या— 475/XXVII(7)/2008 दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एमओयू अवश्य हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

9. उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा डीओएसओ की दरों के आधार पर आगणन तैयार किया जा रहा है तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः इस शर्त के साथ स्वीकृति दी जाती है कि कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम अपने कार्य प्रदर्शिका, वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा डीओएसओ के नियमों का अक्षरशः पालन करेंगे तथा सुनिश्चित करेंगे कि त्रुटिवश कोई फाइनेशियल डुप्लीकेसी हुई हो तो उसका तत्काल निराकरण करेंगे।
10. योजना को इस तरह डिजाइन किया जाय कि सम्पूर्ण कार्य भिन्न-भिन्न ब्लॉकों में सम्पादित कराया जा सके तथा एसपीओ के अर्न्तगत अनुमोदित रु० 5.00 करोड़ के सापेक्ष एक ब्लॉक का कार्य पूर्ण हो सके। जबकि अन्य ब्लॉकों के शेष कार्य हेतु शेष धनराशि की व्यवस्था भारत सरकार की किसी अन्य योजना से कराने का प्रयास किया जायेगा तथा तदोपरान्त की शेष कार्य हेतु प्रस्ताव किया जाय।
11. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या— 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाए।
12. उक्त कार्य के आगणन पर अग्रेत्तर कार्यवाही करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लें कि यदि शासनादेश सं० 571 दिनांक 19.10.2010 के दिशा निर्देशों के क्रम में उक्त कार्य हेतु प्रथम चरण के कार्य की स्वीकृति प्रदान की गयी है तो प्रथम चरण के अर्न्तगत स्वीकृत समस्त कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त यदि प्रथम चरण के अर्न्तगत स्वीकृत राशि में बचत है तो उसे द्वितीय चरण के आगणन में समायोजित कर लिया जाये।
13. आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित करें।
- 2— उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-12 के लेखाशीर्षक-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-09-राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों की स्थापना के मानक मद- 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
- 3— यह आदेश वित्त अनुभाग-3 उत्तराखण्ड शासन के अशा० सं०— 253(P)/XXVII(3)/2016, दिनांक-30, दिसम्बर, 2016 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।
- 4— उक्त स्वीकृति की कम्प्यूटर एलोटमेन्ट आईडी० संलग्न है।

संलग्नक—यथोपरि।

भवदीय,

(डी० सेन्थिल पाण्डेयन)  
सचिव।



संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
3. जिलाधिकारी, नैनीताल।
4. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
5. संबंधित कोषाधिकारी।
6. प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, हल्द्वानी।
7. महाप्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. परियोजना प्रबंधक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0, हल्द्वानी इकाई, हल्द्वानी।
9. बजट प्रकोष्ठ, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. वित्त अनुभाग-3/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
(सुभाष चन्द्र)  
अनु सचिव।